'भारत दुनिया में अवैध सिगरेट का चौथा सबसे बड़ा बाजार'

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात आदि राज्यों में वाणिज्यिक फसलों से जुड़े लाखों किसानों और कृषि कामगारों के प्रतिनिधि गैर लाभकारी संगठन फ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशंस (एफएआईएफए) ने अपनी बजट पूर्व अपील में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अनुरोध किया है कि तंबाकू की फसल को भी अन्य कृषि उत्पादों की तरह ही माना जाए और भारत में वैध तरीके से तैयार तंबाकू उत्पादों पर कर का अतिरिक्त बोझ न डाला जाए क्योंकि इससे तंबाकू किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

कृषि समुदाय निजी हितों के लिए काम करने वाले विभिन्न एनजीओ की ओर से पड़ने वाले दबाव को लेकर बहुत चिंतित है, जिनका एजेंडा है कि भारत में तस्करी वाले सिगरेट के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय तंबाकू उत्पादों की खपत बढ़े क्योंकि इससे विदेशी ब्रांड्स को भारतीय बाजार में पहुंचने में मदद मिलती है। उपभोक्ता बहुत तेजी से सस्ते अवैध और तस्करी कर लाए हुए ब्रांड्स को अपना रहे हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है और भारतीय किसानों की आजीविका खतरे में पड़ रही है। विदेशी फंड पर चल रहे एनजीओ का एजेंडा है कि भारतीय बाजार में तस्करी कर लाए हुए सिगरेट की भरमार हो जाए। इससे भारत अवैध सिगरेट का चौथा सबसे बड़ा बाजार बन गया है, जहां अवैध सिगरेट की मात्रा वैध मात्रा की तिहाई से ज्यादा हो गई है।

कृषि समुदाय ने तंबाकू सेक्टर के लिए आरओडीटीईपी के तहत मिलने वाले लाभ को विस्तार देने की मांग भी की है। इसके तहत मिलने वाला इंसेंटिव विदेश व्यापार नीति के लक्ष्यों के अनुरूप है और इससे भारतीय किसानों के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बराबरी का मौका मिलेगा जिससे देश में विदेशी मुद्रा आएगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी।